



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112023-250174  
CG-DL-E-21112023-250174

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2023/कार्तिक 29, 1945

No. 667]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2023/KARTIKA 29, 1945

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 850(अ).—अध्यक्ष, लोक सभा भर्ती एवं सेवा शर्तें आदेश सं. 185 दिनांक 19 दिसम्बर, 1957 द्वारा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों पर यथा लागू मूल नियमों के नियम 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा लोक सभा सचिवालय (आवासों का आवंटन) नियम, 1974 के अधिक्रमण में लोक सभा सचिवालय के नियंत्रणाधीन आवासों का लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों को आवंटन का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को लोक सभा सचिवालय (आवासों का आवंटन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क. “आवास” से लोक सभा सचिवालय के नियंत्रणाधीन लोक सभा सचिवालय पूल रिहायशी आवास अभिप्रेत है;

- ख. “आवंटन” से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रिहायशी आवास के अधिभोग की अनुज्ञप्ति प्रदान करना अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत, आवंटन की स्वचालित प्रणाली (एएसए) या आवंटन की मैनुअल प्रणाली शामिल है;
- ग. “गैराज का आवंटन” से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार गैराज के अधिभोग की अनुज्ञप्ति प्रदान करना अभिप्रेत है;
- घ. “नुकसान” से आवास या गैराजों के अधिभोगी द्वारा आवास या गैराज के सभी या किसी भाग के दुरुपयोग या उप-किराये पर देने या अधिभोग की दशा में अनुज्ञप्ति फीस के गुणज में लगाया जाने वाला प्रतिकर, अभिप्रेत है;
- ङ. “लोक सभा सचिवालय” से “लोक सभा सचिवालय का कार्यालय” अभिप्रेत है;
- च. “लोक सभा सचिवालय पूल रिहायशी आवास” से वर्तमान में लोक सभा सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी आवास अभिप्रेत है;
- छ. “अधिकारी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक सभा के सचिवालयीय स्टॉफ के संवर्ग में नियुक्त किया गया है, या सम्मिलित किया गया है;
- ज. “आवास के टाइप की पात्रता” से किसी अधिकारी के सम्बन्ध में इन नियमों के अधीन आवास के टाइप, जिसका वह हकदार है, अभिप्रेत है;
- झ. “कर्मचारी” से लोक सभा सचिवालय का कर्मचारी अभिप्रेत है;
- ञ. “परिवार” में आवंटिती की पत्नी या पति, यथास्थिति, और बालक, सौतेले बालक, विधिक रूप से दत्तक लिए गए बालक, माता-पिता, भाई या बहन, जो सामान्य तौर पर आवंटिती के साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हैं, अभिप्रेत है;
- ट. “अतिथि” से आवंटिती के साथ अस्थायी रूप से ठहरने वाला आकस्मिक आगन्तुक अभिप्रेत है;
- ठ. “गृह स्वामित्व रखना” से ऐसा कोई भवन या उसका भाग, जो रिहायशी प्रयोजन के लिए आवंटिती या उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में है, अभिप्रेत है;
- ड. “निकटतम सम्बन्धी” से ऐसे संबंध जैसे दादा, दादी, पोते, पोतियां, ससुर, सास, दामाद, बहू अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत विधिक दत्तक ग्रहण द्वारा स्थापित सम्बन्ध भी शामिल हैं;
- ढ. “अनुज्ञप्ति फीस” से ऐसी फीस अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन आवंटित आवास के सम्बन्ध में मासिक रूप से देय है;
- ण. किसी आवंटन के सम्बन्ध में “दुरुपयोग” से आवंटिती के द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या उसके साथ रहने वाले निकटतम सम्बन्धी द्वारा किसी आवास या किसी सेवक आवास-गृह या गैराज का, इन नियमों के अधीन उपबंधित प्रयोजनों से भिन्न, किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाना, अभिप्रेत है;
- त. “उप-किरायेदारी” से किसी आवंटिती द्वारा लोक सभा सचिवालय पूल रिहायशी आवास का, पूर्णतः या अंशतः भाग अपने परिवार और निकटतम संबंधियों से अन्यथा किसी व्यक्ति को किराये पर देना, अभिप्रेत है;
- थ. “आवास का अभ्यर्पण” से आवंटिती द्वारा आवास के भौतिक अधिभोग के पश्चात् आवंटन अवधि के दौरान अपनी इच्छा से उस आवास को रिक्त करना, अभिप्रेत है;
- द. “स्थानांतरण” से पात्र कार्यालय से अपात्र कार्यालय को स्थानांतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी अपात्र कार्यालय या संगठन में प्रतिनियुक्ति के पद पर नियुक्ति भी शामिल है।

### 3. आवास के लिए पात्र जोन—

लोक सभा सचिवालय (एलएसएस) के सभी कर्मचारी (लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति/संविदा/सह-विस्तारी आधार पर के सिवाय), जो इन नियमों के अधीन पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं और लोक सभा सचिवालय द्वारा आवास के आवंटन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पात्र घोषित किए गए हैं, लोक सभा सचिवालय पूल से आवास के आवंटन के लिए या आवास के प्रतिधारण के लिए पात्र होंगे।

**4. आवास के टाइप के लिए पात्रता/हेतु वर्गीकरण—**

(1) इन नियमों में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई अधिकारी/कर्मचारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए आवास के टाइप के आवंटन हेतु पात्र होगा:—

आवासों का टाइप	वर्तमान ग्रेड पे	पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
I	Rs. 1900	2
II	Rs. 2000, Rs. 2200, Rs. 2400 and Rs. 2800	3,4,5
III	Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800	6,7,8
IV	Rs. 5400 to Rs. 6600	10,11
VA (DII)	Rs. 7600 and Rs. 8000	12
VB (DI)	Rs. 8700 and Rs. 8900	13
VIA (CII)	Rs. 10,000	14
VIB (CI)	Rs. 67000 to Rs. 74999	15 (स्तर में अनुक्रमणिका सं. 1 से 4)
VII	Rs. 75000 to 79999	15 15 (स्तर में अनुक्रमणिका सं. 5 से 8)16
VIII	Rs. 80000 and above	17, 18

(2) विभिन्न टाइप के आवासों के लिए पूर्विकता की तारीख और प्रतीक्षा सूचियों को तैयार करने के लिए संगणना निम्नानुसार की जाएगी:

(क) टाइप 1 से टाइप IV आवासों के संबंध में पूर्विकता तारीख का अवधारण कर्मचारी द्वारा लोक सभा सचिवालय में सेवारंभ की तारीख के आधार पर किया जाएगा और आवास के टाइप के लिए पात्रता का विनिश्चय पे मैट्रिक्स में आवेदक के स्तर के अनुसार किया जाएगा:

परंतु इस प्रवर्ग के अधीन किसी आवेदक को, उसकी पात्रता के टाइप से एक टाइप नीचे के आवास हेतु आवेदन करने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(ख) टाइप 1 से टाइप IV के आवासों के लिए परस्पर वरिष्ठता पर निम्नलिखित कारकों के आधार पर विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) जहां दो या अधिक आवेदकों की लोक सभा सचिवालय में सेवारंभ की तारीख एक समान है, वहां स्तर में उच्चतर स्तर वेतन वाला आवेदक प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ होगा;

(ii) जहां दो या अधिक आवेदकों की लोक सभा सचिवालय में सेवारंभ की तारीख और स्तर में वेतन एक समान है, वहां पहले सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक पर पूर्विकता प्रदान की जा सकेगी।

(ग) टाइप VA और ऊपर के आवासों के संबंध में पूर्विकता तारीख का अवधारण उस तारीख के आधार पर किया जाएगा, जिससे आवेदक लोक सभा सचिवालय में पे मैट्रिक्स में निरंतर संगत वेतन आहरित कर रहा है।

(घ) टाइप VA और ऊपर के आवासों के लिए परस्पर वरिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित कारकों के आधार पर विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) जहां दो या अधिक आवेदकों की पूर्विकता तारीख एक समान है, वहां स्तर में उच्चतर स्तर वेतन वाला आवेदक प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ होगा;

(ii) जहां दो या अधिक आवेदकों की पूर्विकता तारीख और स्तर में वेतन एक समान है, वहां वह आवेदक, जिसने लोक सभा सचिवालय में पहले सेवारंभ की है, प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ होगा; और

- (iii) जहां दो या अधिक आवेदकों की पूर्विकता तारीख, स्तर में वेतन और लोक सभा सचिवालय में सेवारंभ करने की तारीख एक समान है, वहां पहले सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक को बाद में सेवानिवृत्त होने वाले आवेदक पर पूर्विकता प्रदान की जा सकेगी।

(3) टाइप V और ऊपर के आवासों के लिए हकदार आवेदक, इस शर्त के अधीन कि ऐसा कोई आवास टाइप IV आवासों से निम्न नहीं होगा, अपनी हकदारी से निम्न आवास हेतु आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे।

(4) रक्षा बल या किसी अन्य संगठन में पूर्व सेवाओं का लाभ पूर्विकता की तारीख की संगणना के प्रयोजनों हेतु नहीं दिया जाएगा।

(5) प्रतीक्षा सूची में परस्पर वरिष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए वैयक्तिक वेतन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(6) प्रैक्टिसबंदी भत्ता, सेना सेवा वेतन या वेतन के ऐसे किसी अन्य संघटक पर प्रतीक्षा सूची में परस्पर वरिष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

## 5. आवास के लिए आवेदन

(1) पात्र लोक सभा सचिवालय कर्मचारी लोक सभा सचिवालय इंटरनेट पर उस आवास के आवंटन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन पात्र है और इन नियमों के अनुसरण में पूर्विकता के अनुसार आवास, जिसकी हकदारी है, को आवंटित के अधिमान को विचार में रखकर प्रस्तावित किया जाएगा।

(2) आवेदन करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त आवेदनों को संबंधित एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा और उन आवेदनों पर इन नियमों के अनुसार आवंटन के लिए निबंधन और शर्तों के अधीन आवेदन करने के अगले चक्र में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

(3) आवेदक, ऑनलाइन आवेदन पत्र में विभिन्न विवरण प्रस्तुत करेगा जिन्हें विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और आवेदन में कोई विसंगति होने या आवेदन में कोई गलत जानकारी देने की दशा में, आवेदक और सत्यापन करने वाला अधिकारी गलत जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत, यदि आवंटन गलत जानकारी के आधार पर किया गया था तो आवास का आवंटन रद्द करना, भी शामिल है।

(4) अधिवर्षिता की तारीख के छह मास के भीतर आवास के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 6. विभिन्न टाइप के आवास के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करना –

(1) टाइप VII और टाइप VIII आवास को छोड़कर प्रत्येक टाइप के आवास के लिए एक एकीकृत प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।

(2) किसी एकीकृत प्रतीक्षा सूची में आवास के लिए आरंभिक आवेदन करने वाले या पहले से आवेदन कर चुके आवेदकों के नाम के साथ-साथ आवास के परिवर्तन के लिए आवेदन करने वालों के नाम भी होंगे और यह सूची किसी एक टाइप के आवास की हकदारी के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) टाइप V और ऊपर के आवास के लिए हकदार आवेदकों के नाम नीचे के टाइपों के आवास, जिनके लिए वे हकदार हैं, की सभी एकीकृत प्रतीक्षा सूचियों में सम्मिलित किए जाएंगे।

(4) टाइप II, टाइप III और टाइप IV के आवास के हकदार आवेदकों के नाम एक टाइप नीचे के आवास, जिनके लिए वे हकदार हैं, की सभी एकीकृत सूचियों में सम्मिलित किए जाएंगे।

## 7. एकीकृत प्रतीक्षा सूची से उन आवेदकों के नाम हटाना, जो आवास लेने के प्रति गंभीर नहीं हैं –

ऐसे आवेदक जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान न तो अपने वैयक्तिक आंकड़ें अद्यतन किए हैं, और न ही किसी आवास के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है, उनके नाम स्वतः एकीकृत प्रतीक्षा सूची से हट जाएंगे:

परन्तु ऐसा कोई आवेदक जिसका नाम हट जाता है, ऑनलाइन विहित आवेदन पत्र भर कर पुनः अपना नाम सूचीबद्ध कर सकता/सकती है और ऐसे आवेदक पर आवास से संबंधित टाइप की एकीकृत प्रतीक्षा सूची में विचार किया जाएगा।

**8. आवास के आवंटन का प्रस्ताव —**

(1) इन नियमों में यथाउपबन्धित के सिवाय, सभी टाइप के रिक्त होने वाले आवासों का, आवंटन की स्वचालित प्रणाली (एसएएस) द्वारा इन नियमों के अधीन आवास के ऐसे टाइप के लिए एकीकृत प्रतीक्षा सूची में से आरंभिक आवंटन या आवास परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को आवंटन किया जाएगा।

(2) लोक सभा सचिवालय आपात परिस्थितियों में, जब आवंटिती के अधिभोग में जो आवास है, उसे रिक्त किया जाना अपेक्षित है, उसे उपलब्धता के अध्यधीन, उसी टाइप का दूसरा आवास या आवंटिती के अधिभोग में जो आवास है, उससे ठीक नीचे के टाइप का आवास आवंटित कर सकेगा।

**9. अवधि जिसके लिए आवंटन बना रहता है—**

कोई आवंटन, आवंटिती द्वारा इसे स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और लोक सभा सचिवालय सेवा में बने रहने या तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि—

- (क) इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय रियायती अवधि की समाप्ति के पश्चात् आवंटिती लोक सभा सचिवालय में सेवा में बना रहता है;
- (ख) यह लोक सभा सचिवालय/संपदा अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया हुआ समझा गया है;
- (ग) यह आवंटिती द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया है;
- (घ) आवंटिती आवास के अधिभोग में नहीं बना रहता है।

**10. आवंटन को स्वीकार करना—**

किसी आवास के आवंटन का कोई प्रस्ताव स्वचालित प्रणाली के माध्यम से या आवंटन की हस्त प्रणाली द्वारा, यथास्थिति, आवास के आवंटन की तारीख से आठ दिनों के भीतर आवंटिती द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

**11. स्वीकृति के पश्चात् प्रक्रिया—**

(1) आवंटित आवास स्वीकार किए जाने के पश्चात्, आवंटिती केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से या किसी अन्य अनुरक्षण अभिकरण से, यथास्थिति, स्वीकृति पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर आवास का भौतिक कब्जा लेगा और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या कोई अन्य अनुरक्षण अभिकरण, यथास्थिति, आवंटित आवास का कब्जा आवंटिती को देगा।

(2) यदि आवंटित आवास तुरन्त अधिभोग के लिए तैयार नहीं हैं तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या कोई अन्य अनुरक्षण अभिकरण लोक सभा सचिवालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर, तकनीकी अधिभोग रिपोर्ट, आवंटिती को जारी करेगा।

(3) आवास के अधिभोग के लिए तैयार हो जाने और रहने योग्य स्थिति में आवंटिती को कब्जा दे दिए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आवंटिती को भौतिक अधिभोग रिपोर्ट जारी करेगा।

**12. आवंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार करना या स्वीकार करने के पश्चात् आवंटित आवास के अधिभोग में विफल रहना—**

(1) यदि कोई आवंटिती किसी रिहायशी आवास के आवंटन की तारीख से आठ दिन के भीतर उक्त आवास को स्वीकार करने में विफल रहता है या प्राधिकार पत्र की प्राप्ति की तारीख से पांच कार्य दिवस के भीतर उस आवास का कब्जा लेने में विफल रहता है तो वह, एक मास की सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के अध्यधीन, आवंटन अस्वीकार करने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए आवास के आवंटन के लिए आवेदन करने से विवर्जित हो जाएगा।

(2) आवंटन अस्वीकार करने की तारीख की संगणना आवंटन की तारीख से की जाएगी।

(3) यदि निचले टाइप के आवास का अधिभोग करने वाला कोई आवंटिती इन नियमों के अधीन पात्र उस टाइप के आवास के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार करता है जिसका वह पात्र है तो उसे पहले से आवंटित आवास में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

परंतु ऐसा आवंटिती ऐसे आवंटन को अस्वीकार करने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए दूसरे आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

### 13. असुरक्षित या जोखिम के आधार पर आवास का आवंटन—

(1) कोई आवंटिती, जिसका रिहायशी आवास असुरक्षित या जोखिमपूर्ण है, सम्बन्धित अनुरक्षण अभिकरण को ऐसे आवास को रहने के लिए असुरक्षित या जोखिमपूर्ण घोषित करने के लिए आवेदन कर सकेगा/सकेगी और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का अधिकारी जो कार्यपालक इंजीनियर के रैंक से नीचे का न हो या किसी अन्य अनुरक्षण अभिकरण का समतुल्य अधिकारी, अपनी संतुष्टि करने पर कि सम्बन्धित आवास असुरक्षित या जोखिमपूर्ण है, लोक सभा सचिवालय को लिखित रूप में, इस प्रकार की घोषणा का प्रमाण-पत्र जारी करेगा और आवास की असुरक्षित आवास रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

(2) किसी आवास को असुरक्षित या जोखिमपूर्ण घोषित करने पर आवंटिती को वैकल्पिक आवास का आवंटन स्वचालित प्रणाली या आवंटन की मैनुअल प्रणाली, जो भी लागू हो, के माध्यम से किया जाएगा।

(3) उन मामलों में जहां किसी वैयक्तिक आवास को सरकारी रिहायशी कॉलोनी में असुरक्षित या जोखिमपूर्ण घोषित किया जाता है, उसी टाइप के आवास का अनुकल्पी आवंटन पूर्विकता के निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा:

- (क) आवंटन के लिए उसी परिक्षेत्र में या निकटतम परिक्षेत्र में रिक्त आवास चिन्हित किए जाएंगे जहां ऐसे अधिभोगियों को उसी टाइप के आवास में एकीकृत (आरंभिक/परिवर्तन) प्रतीक्षा सूची में पूर्विकता दी जाएगी;
- (ख) कोई आवंटिती, जो विशिष्ट तल के अधिभोग में है, उसी तल या आवास के ऊपर के टाइप के आवंटन के लिए आवेदन कर सकेगा और तदनुसार आवंटन किया जाएगा;
- (ग) ऐसे असुरक्षित या जोखिमपूर्ण गृहों की संख्या के बराबर संख्या में चिन्हित रिक्त आवासों को ए.एस.ए. में आवंटन के लिए रखा जाएगा।

### 14. एक दूसरे से विवाहित आवंटितियों की पात्रता—

(1) यदि सरकारी सेवक के पति या पत्नी को पहले से ही कोई आवास आवंटित है तो लोक सभा सचिवालय के किसी भी कर्मचारी को इन नियमों के अधीन तब तक कोई आवास आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आवास अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता;

परंतु यह उप-नियम वहां लागू नहीं होगा जहां पति और पत्नी निम्नलिखित के अनुसरण में अलग-अलग निवास कर रहे हैं—

- (i) किसी न्यायालय द्वारा किया गया न्यायिक पृथक्करण का कोई आदेश; या
- (ii) किसी न्यायालय द्वारा जिसमें पति या पत्नी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए फाइल की गई याचिका लंबित है कार्यवाहियों के निपटारे के लिए विवादकों को विरचित करने और अभिलिखित करने के लिए दिया गया कोई आदेश, पति या पत्नी ने कोई वचनबंध प्रस्तुत किया है कि वह अपने पति या अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन की दशा में तुरन्त उसे आवंटित आवास को अभ्यर्पित कर देगी या कर देगा।

(2) जहां इन नियमों के अधीन आवंटित आवास दो आवंटितियों के अलग-अलग अधिभोग में हों और यदि वे एक-दूसरे से विवाह करते हैं तो विवाह के एक महीने के भीतर किसी एक आवास को अभ्यर्पित कर देंगे।

(3) जहां उप-नियम (2) की अपेक्षाओं के अनुसार कोई एक आवास अनुज्ञेय अवधि के भीतर अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है तो ऐसी अवधि के अवसान पर निचले टाइप के आवास के आवंटन को रद्द किया समझा जाएगा और यदि दोनों आवास एक ही टाइप के हों तो इनमें से एक का आवंटन, जैसा लोक सभा सचिवालय विनिश्चित करे, इस अवधि के समाप्त होने पर रद्द किया गया समझा जाएगा।

(4) जहां पति और पत्नी दोनों लोक सभा सचिवालय के अधीन नियोजित हों तो इन नियमों के अधीन दोनों की आवास आवंटन सम्बन्धी हकदारी पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

(5) उप-नियम (1) से उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, (i) जहां पति या पत्नी, जो इन नियमों के अधीन आवास का/की आवंटिती है, को तत्पश्चात् सामान्य पूल अथवा अन्य सरकारी कार्यालय से आवास आवंटित किया जाता है तो वह ऐसे आवंटन के एक मास के भीतर किसी एक आवास को अभ्यर्पित कर देगा/देगी: परंतु यह खंड ऐसे पति और पत्नी पर लागू नहीं होगा जो न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक पृथक्करण आदेश के अनुसरण में अलग-अलग रह रहे हैं। (ii) जहां दो आवंटिती, अलग-अलग आवास के अधिभोग में हैं, एक को इन नियमों के अधीन आवास आवंटित है और दूसरे को सामान्य पूल अथवा अन्य सरकारी कार्यालय से आवास आवंटित है और वे यदि एक-दूसरे से विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह के एक मास के भीतर उन दोनों में से कोई एक किसी एक आवास का अभ्यर्पण करेगा।

(6) यदि उप-नियम (5) की अपेक्षाओं के अनुसार कोई आवास अभ्यर्पित नहीं किया जाता है तो लोक सभा सचिवालय में आवास का आवंटन, ऐसी अवधि की समाप्ति पर रद्द किया हुआ समझा जाएगा।

### 15. महिला कर्मचारियों को आवंटन (महिला पूल) —

(1) महिला पूल कोटा के तहत आवंटन केवल टाइप I से टाइप Vए तक किया जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए टाइप I से टाइप Vए आवास के लिए पृथक एकीकृत प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी।

(2) लोक सभा सचिवालय पूल में टाइप I से टाइप Vए आवासों में से 10 प्रतिशत रिक्त आवास महिला कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे जिनमें से एकल महिला कर्मचारियों और विवाहित महिला कर्मचारियों के लिए क्रमशः 1:2 के अनुपात में आवंटन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए- (i) "विवाहित महिला कर्मचारी" से ऐसी महिला कर्मचारी अभिप्रेत है जिसका विवाह अस्तित्व में है और जो अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक नहीं हुई है; और (ii) "एकल महिला कर्मचारी" से कोई अविवाहित महिला कर्मचारी अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत विधवा, बालकों सहित या रहित भी शामिल हैं।

(3) इस नियम के अधीन आवास के आवंटन के लिए पात्र महिला कर्मचारियों की परस्पर-ज्येष्ठता नियमानुसार अवधारित की जाएगी।

(4) सभी महिला कर्मचारी, जो लोक सभा सचिवालय पूल आवास आवंटन में आवास के लिए अन्यथा पात्र हैं, महिला पूल से आवंटन के लिए भी पात्र होंगी।

(5) महिला कर्मचारी, जो पहले से ही आवास के अधिभोग में है उसी टाइप में परिवर्तन के लिए या उच्चतर टाइप के आवास के आवंटन के लिए भी, अपनी बारी पर, महिला पूल से और सामान्य पूल से पात्र होंगी।

(6) यदि महिला पूल के तहत कर्मचारियों को किए जाने वाले आवंटन और आरक्षित कोटे के तहत अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों को किए जाने वाले आवंटन के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो आवास का आवंटन पहले अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी को और तत्पश्चात् महिला कोटा के तहत महिला कर्मचारी को किया जाएगा।

(7) एक महिला कर्मचारी जिसे सामान्य कोटे से आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के लिए लोक सभा सचिवालय के आवास पूल से विवर्जित कर दिया गया था, विवर्जन की अवधि के दौरान आरक्षित कोटे से आवंटन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा और विपर्ययेन।

(8) यदि कोई एकल महिला कर्मचारी आवंटन के लिए पात्र नहीं है, तो उनके लिए आरक्षित कोटा विवाहित महिला कर्मचारी को आवंटित किया जा सकता है और यदि कोई विवाहित महिला कर्मचारी आवंटन के लिए पात्र नहीं है तो उनके लिए आरक्षित कोटा एकल महिला कर्मचारी को आवंटित किया जा सकता है।

### 16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवंटन में आरक्षण—

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आवंटन में टाइप I आवास और टाइप II आवास में दस प्रतिशत और टाइप III तथा टाइप IV आवास में पांच प्रतिशत आरक्षण होगा।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को, क्रमशः, 2:1 के अनुपात में टाइप I से टाइप IV में से रिक्त आवासों का आवंटन किया जाएगा।

(3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए टाइप I से टाइप IV आवास के लिए पृथक एकीकृत प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी।

- (4) एकीकृत प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जनजातियों का कोई आवेदक नहीं होने की दशा में, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा अनुसूचित जातियों के आवेदक को आवंटित किया जा सकेगा और इसकी विपरीत स्थिति में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटा अनुसूचित जनजातियों के आवेदक को आवंटित किया जा सकेगा।
- (5) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदक, जो पहले से ही लोक सभा सचिवालय पूल आवास के अधिभोग में हैं, इस नियम के अधीन उनके लिए आरक्षित कोटे में से उच्चतर टाइप के आवास के आवंटन के लिए पात्र होंगे।
- (6) टाइप I और टाइप II आवास के सम्बन्ध में एक 60 बिन्दु रोस्टर प्रणाली होगी और बिन्दु संख्या 10, 20, 40 और 50 के रिक्त आवास अनुसूचित जातियों के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे और बिन्दु संख्या 30 और 60 के रिक्त आवास अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे।
- (7) टाइप III और टाइप IV आवास के सम्बन्ध में एक 60 बिन्दु रोस्टर प्रणाली होगी और बिन्दु संख्या 20 और 40 के रिक्त आवास अनुसूचित जातियों के आवेदकों को और बिन्दु संख्या 60 का रिक्त आवास अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को आवंटित किया जाएगा।
- (8) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक सामान्य पूल से आवंटन के लिए भी पात्र होंगे।
- (9) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक, जिन्हें सामान्य कोटा से किये गये आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के कारण लोक सभा सचिवालय के आवास पूल के लिए विवर्जित कर दिया गया है, उन्हें विवर्जन की अवधि के दौरान आरक्षित कोटा से आवंटन के लिए भी पात्र नहीं समझा जाएगा; और इसके विपरीत यदि आवेदक को आरक्षित कोटा से आवंटन के लिए विवर्जित कर दिया गया है, तो उन्हें सामान्य कोटा में आवंटन के लिए भी अपात्र माना जाएगा।
- (10) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक अपने आवास के आवंटन के आवेदन में इस तथ्य का उल्लेख करेंगे कि क्या वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, जिसका सत्यापन अभिहित अधिकारी आवेदक द्वारा आवास के आवंटन को स्वीकार करने के समय उसके रिकॉर्ड से करेगा।

#### 17. अधिशेष आवास का आवंटन

किसी भी टाइप के अधिशेष आवास की उपलब्धता की दशा में, आवेदक को उसकी हकदारी वाले टाइप की तुलना में निम्नतर टाइप के किसी आवास का आवंटन उसे आवंटित टाइप की सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर आवंटित किया जा सकता है।

#### 18. विवाह या सामाजिक प्रयोजनों के लिए आवास का अस्थायी आवंटन

विवाह या सामाजिक प्रयोजनों के लिए आवास (यदि उपलब्ध हो) का अस्थायी आवंटन लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

#### 19. आवास प्रतिधारण की रियायती अवधि—

कोई आवंटिती, इन नियमों में अधिकथित शर्तों के अधीन, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने पर स्तम्भ (3) में उसके सामने की कई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आवास को प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात हो सकेगा, बशर्ते कि आवास आवंटिती या उसके परिवार के सदस्यों के लिए सद्भाविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो।

क्रम संख्या	घटना	आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञेय अवधि
(1)	(2)	(3)
(एक)	सेवा से त्यागपत्र, सेवा से पदच्युति या हटाया जाना, सेवा की समाप्ति या अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत अनुपस्थिति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति {सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अधीन} और अनियमित सरकारी सेवकों के लिए।	एक मास सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर



(दो)	सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति, सेवांत छुट्टी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति [एफआर 56 (जे) के अधीन] संगठनों के आरंभिक गठन के दौरान ऐसे अपात्र कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्ति, तकनीकी त्यागपत्र, पुनर्नियोजन पर आवंटिती की मृत्यु (सेवानिवृत्ति पर प्रतिधारण उपभोग पर विचार किए बिना) और ऐसे किसी आवंटिती की मृत्यु, जो नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं।	छह मास सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर
(तीन)	विद्यमान स्थान से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरण, किसी अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण, भारत में विदेशी सेवा पर जाने भारत में अस्थायी स्थानांतरण या भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरण या भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति।	सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर दो मास + दोगुने अनुज्ञप्ति शुल्क पर छह मास
(चार)	आवंटिती की मृत्यु के मामले में, पात्र पति-पत्नी या प्रतिपाल्य को	सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर बारह मास और आगे बारह मास के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर, बशर्ते कि मृतक आवंटिती या परिवार का कोई सदस्य दिल्ली/एनसीआर में किसी गृह का स्वामी न हो।
(पाँच)	भारत से बाहर अध्ययन के लिए छुट्टी	छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए, किन्तु जो छह मास से अधिक की न हो
(छह)	भारत में अध्ययन के लिए छुट्टी	छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए, किन्तु जो छह मास से अधिक की न हो
(सात)	चिकित्सा आधार पर छुट्टी	छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए

## 20. समान टाइप वाले या हकदारी वाले उच्चतर टाइप के आवास में परिवर्तन—

- (1) कोई आवंटिती, जिसे इन नियमों के अधीन कोई आवास आवंटित किया गया है, आरंभिक आवंटन के अधीन आवंटित आवास का भौतिक कब्जा लेने के पश्चात् ही उसी टाइप के दूसरे आवास के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (2) आवंटिती को उसी टाइप के आवास में केवल एक परिवर्तन की अनुमति होगी।
- (3) कोई आवंटिती, जो पहले से आवंटित आवास के परिवर्तन का आशय रखता/रखती है, लोक सभा सचिवालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करेगा/करेगी और उसके पश्चात् ऐसे आवंटिती का नाम सम्बन्धित टाइप की एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
- (4) टाइप I से लेकर टाइप VIबी तक के सम्बन्ध में आवास के परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा सूची में आवंटितियों की पूर्विकता की तारीख या परस्पर ज्येष्ठता आरंभिक आवंटन से यथानुसार लागू होगी।
- (5) उसी टाइप के आवास का परिवर्तन इन नियमों के अनुसार, पूर्विकता के अनुसार और आवंटिती के अधिमान को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया जाएगा:

परंतु किसी आवंटिती को अधिवर्षिता की तारीख के छह मास के भीतर उसी टाइप के आवास में कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा।

- (6) यदि कोई आवंटिती उसे प्रस्तावित आवास के परिवर्तन को ऐसे प्रस्ताव या आवंटन के जारी होने के आठ दिनों के भीतर स्वीकार करने में विफल रहता/रहती है, तो उसके उसी टाइप के आवास के परिवर्तन हेतु किसी आवेदन पर उस टाइप के आवास को स्वीकार नहीं किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

(7) यदि कोई आवंटिती, जो आवास के परिवर्तन को स्वीकार करने के पश्चात् उसका कब्जा लेने में विफल रहता/रहती है, पहले से उसके कब्जे में आवास के लिए जिसका आवंटन अस्तित्व में रहेगा, के सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त, उस पर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे आवास के लिए एक मास का अनुज्ञप्ति शुल्क भारित किया जाएगा:

परंतु यदि विहित समयवधि के भीतर परिवर्तन पर प्रस्तावित आवास को रहने योग्य बनाने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग विफल रहता है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यपालक इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र दिलाया जाएगा और ऐसे मामलों में मध्यवर्ती अवधि के लिए आवंटितियों को अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

(8) जहां कोई आवंटिती, जो किसी आवास के अधिभोग में है, को अन्य आवास आवंटित कर दिया जाता है और वह नये आवास में अधिभोग रखता है, तो पूर्वतर आवास का आवंटन नए आवास के भौतिक कब्जे की तारीख से रद्द समझा जाएगा:

परंतु ऐसे अधिभोग की तारीख से, आवंटिती पूर्ववर्ती आवास को नए आवंटित आवास में स्थानांतरण करने हेतु तीस दिन की अवधि के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर प्रतिधारित कर सकेगा।

परंतु यह और कि यदि पूर्ववर्ती आवास तीस दिन की अवधि के भीतर रिक्त नहीं किया जाता है तो आवंटिती नए आवास के भौतिक कब्जे की तारीख से 31 वें दिन के प्रभाव से पूर्ववर्ती आवास, फर्नीचर और बगीचा के अधिभोग और उपयोग के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथावधारित हर्जाने का भुगतान करने के लिए दायी होगा और इन नियमों के अधीन परिवर्तन द्वारा आवंटित आवास रद्द हुआ समझा जाएगा।

(9) आवंटिती आवास के परिवर्तन के लिए आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित करेगा कि वह पुनरीक्षित हकदारी के साथ-साथ आवास के ऐसे परिवर्तन को शासित करने वाली शर्तों के आधार पर आवास के टाइप के लिए हकदार बना हुआ है और सम्बन्धित आवंटन प्राधिकारी या सम्पदा कार्यालय आवेदक की स्वीकृतिपत्र को स्वीकार करने से पूर्व इस तथ्य का सत्यापन करेगा।

(10) इस नियम के अधीन किसी आवंटिती को आवास का कोई परिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा यदि आवंटिती के विरुद्ध उप-किरायेदारी के आरोप संबंधी कोई जांच चल रही है।

## 21. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की घटना होने पर आवास का परिवर्तन—

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी आवंटिती को उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर आवास का परिवर्तन अनुज्ञात हो सकेगा यदि वह ऐसी घटना के छह मास के भीतर परिवर्तन के लिए आवेदन करता/करती है परंतु ऐसा परिवर्तन उसी टाइप के आवास के लिए उसी तल पर और उसी क्षेत्र में किया जाएगा जहां आवंटिती को पहले से ही आवास आवंटित है।

## 22. पड़ोसियों के मध्य झगड़े के मामले में आवंटितियों का स्थानांतरण—

(1) सरकारी कालोनियों में पड़ोसियों के मध्य झगड़ों से सम्बन्धित किसी शिकायत की विस्तृत जांच आवास का अनुरक्षण करने वाले अधीक्षण इंजीनियर (सिविल), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी और वह लोक सभा सचिवालय को अपनी सिफारिशें देगा।

(2) इस नियम के अधीन दोषी पाये जाने वाले आवंटिती को उसी परिक्षेत्र में लेकिन ऐसे आवंटिती से दूरी पर जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ था, या दूसरे परिक्षेत्र में सुदूर या समीप अवस्थिति या अपराध की प्रकृति या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य आवास में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(3) ऐसा आवंटिती, जो अन्य स्थान पर स्थानांतरित होकर भी अपने पड़ोसियों के साथ पुनः झगड़ा करता है तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और उसे अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आवास के आवंटन से एक से दो वर्षों तक की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:

परंतु यदि आवंटिती, जिसे इस उप-नियम के अधीन विवर्जित किया गया है, तत्पश्चात् आवंटन पर पुनः अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करता/करती है और दोषी पाया जाता है तो उसे आगे की अवधि के लिए स्थायी रूप से आवास के आवंटन के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और ऐसी घोषणा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी।

### 23. किसी आवंटिती की मृत्यु के मामले में कतिपय व्यक्ति के नाम में आवास का नियमितिकरण या अनुकल्पी आवास का आवंटन –

- (1) किसी आवंटिती की मृत्यु होने पर उसी आवास का मृतक के पति-पत्नी या प्रतिपाल्य के नाम पर, यदि पति-पत्नी या प्रतिपाल्य इसके लिए हकदार हैं, नियमितिकरण किया जा सकेगा।
- (2) यदि, पति-पत्नी या प्रतिपाल्य मृतक आवंटिती को आवंटित आवास से निम्नतर टाइप के आवास के हकदार हैं तो किसी अनुकल्पी हकदारी वाले टाइप के आवास का पति-पत्नी या प्रतिपाल्य के नाम पर नियमितिकरण किया जा सकेगा।
- (3) यदि, पति-पत्नी या प्रतिपाल्य, मृतक आवंटिती को आवंटित आवास से उच्चतर टाइप के आवास के हकदार हैं तो किसी अनुकल्पी हकदारी वाले टाइप के ठीक एक नीचे टाइप का आवास, पति-पत्नी या प्रतिपाल्य को, अधिकतम टाइप V के आवास के अध्यक्षीन, सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने पर या निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर आवंटित किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) पति या पत्नी या प्रतिपाल्य आवंटिती की मृत्यु से पहले कम से कम तीन वर्ष से मृत आवंटिती के साथ रह रहा था/रह रही थी और उसने इस अवधि के लिए गृह किराया भत्ता नहीं लिया है और यदि ऐसा पति या पत्नी या प्रतिपाल्य लोक सभा सचिवालय की सेवा में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रहा/रही है और उसने लोक सभा सचिवालय की सेवा में शामिल होने की तारीख से गृह किराया भत्ता नहीं लिया है।
- (ii) आवंटिती की मृत्यु होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर, पति/पत्नी या प्रतिपाल्य (वार्ड) लोक सभा सचिवालय की सेवा में शामिल होता है और अधिभोग में आवास को रिक्त नहीं किया गया है।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजन के लिए “वार्ड” के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे- (क) लोक सभा सचिवालय में कार्यरत विवाहित पुत्री, इस बात के होते हुए भी कि मृतक आवंटिती का एक पुत्र भी है जो कि लोक सभा सचिवालय में कार्यरत है और अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने की स्थिति में है; (ख) लोक सभा सचिवालय में कार्यरत पुत्र-वधु।

- (iii) आवास के नियमितिकरण/ वैकल्पिक आवास के आवंटन के अनुरोध पर उस स्थिति में विचार किया जा सकता है जब आवंटिती की मृत्यु के बाद पति या पत्नी/वार्ड को लोक सभा सचिवालय में रोजगार मिलता है, बशर्ते कि आवंटिती की मृत्यु होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी नियुक्ति हुई हो और अधिभोग में आवास को खाली न किया गया हो;
- (iv) उपरोक्त रियायत उन मामलों में दी जाएगी जहां मृतक अधिकारी या उसके पति/पत्नी/ वार्ड के पास दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई घर नहीं है;
- (v) मृतक आवंटिती पर लाइसेंस शुल्क/हर्जाना की कोई राशि बकाया नहीं है;
- (vi) पति/पत्नी या वार्ड की पूर्विकता की तारीख पर विचार किए बिना नियमों के तहत आवास के नियमितिकरण या वैकल्पिक आवास के आवंटन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (vii) आवंटिती की मृत्यु के पश्चात या उसके पति/पत्नी या वार्ड की लोक सभा सचिवालय की सेवा में नियुक्ति होने की तारीख से आवास के प्रतिधारण की स्वीकार्य अवधि समाप्त होने से पहले, इनमें से जो भी बाद में हो, नियमितिकरण या वैकल्पिक आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (viii) आवंटित आवास के नियमितिकरण या वैकल्पिक आवास के आवंटन हेतु आवेदन देने से पहले, मृतक आवंटिती के अधिभोग में आवास के सम्बन्ध में सभी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
- (ix) इन नियमों के अनुसार, पति/पत्नी या वार्ड के पक्ष में आवास के नियमितिकरण की तारीख को पति/पत्नी या वार्ड को मिलने वाले आवास का प्रकार निर्धारित करने के लिए उनके वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।
- (x) पति/पत्नी या वार्ड के नाम पर वैकल्पिक आवंटन, जहां तक सम्भव हो, उसी क्षेत्र में किया जाएगा, और ऐसा संभव न होने पर, उसके निकटतम क्षेत्र में किया जाएगा।

- (xi) ऐसे वार्ड, जिसके नाम पर वैकल्पिक आवास का नियमितिकरण किया जाना है, इस आशय का एक शपथपत्र देगा कि उसे आवंटित आवास का नियमितिकरण होने या वैकल्पिक आवास का आवंटन होने के पश्चात् मृतक आवंटिती का पति/पत्नी उसके साथ रहेगा/रहेगी।

**24. सेवानिवृत्ति के मामले में किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर वैकल्पिक आवास का आवंटन या आवास का नियमितिकरण -**

- (1) किसी आवंटिती की सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि सेवानिवृत्त आवंटिती का पति/पत्नी या वार्ड पात्र हैं, तो सेवानिवृत्त आवंटिती के पति/पत्नी या वार्ड के नाम पर लोक सभा सचिवालय पूल के उसी आवास का नियमितिकरण किया जा सकेगा।
- (2) यदि, पति/पत्नी या वार्ड, सेवानिवृत्त आवंटिती को आवंटित आवास से निम्नतर श्रेणी के आवास के पात्र हैं तो पति/पत्नी या वार्ड के नाम पर पात्रता की श्रेणी के किसी वैकल्पिक आवास का नियमितिकरण किया जा सकेगा।
- (3) यदि, पति/पत्नी या वार्ड, सेवानिवृत्त आवंटिती को आवंटित आवास से उच्चतर श्रेणी के आवास के पात्र हैं, तो पति/पत्नी या वार्ड को अधिकतम श्रेणी V के आवास के आवंटन की शर्त के अन्तर्गत और सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करने पर तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पात्रता की श्रेणी से नीचे वाली श्रेणी का आवास आवंटित किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) पति/पत्नी या वार्ड, आवंटिती की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन वर्ष पहले से सेवानिवृत्त आवंटिती के साथ रह रहे हों और इस अवधि के लिए उन्होंने आवास किराया भत्ता प्राप्त न किया हो और यदि ऐसे पति/पत्नी या वार्ड तीन वर्ष से कम की अवधि से लोक सभा सचिवालय की सेवा में हैं और उन्होंने लोक सभा सचिवालय की सेवा में अपना पदग्रहण करने की तारीख से आवास किराया भत्ता प्राप्त न किया हो।
- (ii) पति/पत्नी या वार्ड ने आवास को प्रतिधारित करने की अनुज्ञेय अवधि के भीतर लोक सभा सचिवालय में सेवा आरम्भ कर ली हो और अधिभोग में आवास को रिक्त न किया गया हो।

- (4) एक से अधिक पात्र वार्ड होने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के पास अपने वाइर्स में से किसी एक वार्ड का चयन करने का विकल्प होगा।

**स्पष्टीकरण -** इस नियम के प्रयोजन के लिए, "वाइर्स" के अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (क) लोक सभा सचिवालय में कार्यरत विवाहित पुत्री, इस बात के होते हुए भी कि सेवानिवृत्त होने वाले आवंटिती का एक पुत्र भी है जो कि लोक सभा सचिवालय में सेवारत है और अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने की स्थिति में है।
- (ख) लोक सभा सचिवालय में कार्यरत पुत्र-वधू।

**25. वैकल्पिक आवास या नियमितिकरण के लिए अग्रह्यता -**

वैकल्पिक आवास के लिए आवंटन या नियमितिकरण की सुविधा उपरोक्त नियम 23 और 24 के अधीन निम्नलिखित मामलों में ग्राह्य नहीं होगी-

- (क) जहां आवंटिती या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर दिल्ली/एनसीआर में कोई आवास हो : बशर्ते पति/पत्नी या वार्ड के नाम पर पात्रता की श्रेणी से एक श्रेणी नीचे के आवास का या उसी श्रेणी के आवास का नियमितिकरण किया जा सकेगा जिसकी पूर्विकता की तारीख मृतक आवंटिती की मृत्यु की तारीख को या सेवानिवृत्त होने वाले आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के अन्तर्गत आती है, ऐसे आवंटितियों जिनके नाम पर दिल्ली/एनसीआर में कोई आवास है को, आवंटिती पर लागू ऐसी शर्तों और लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास का आवंटन किया जाएगा;
- (ख) जहां आवंटिती मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख को या उससे पूर्व, किसी कारण से, आवास के आवंटन के लिए अपात्र हो गया है।
- (ग) लोक सभा सचिवालय से त्यागपत्र देने की स्थिति में।

- (घ) ऐसे मामले में जहां आवंटिती के पास लोक सभा सचिवालय पूल का आवास था और वार्ड/पति/पत्नी लोक सभा सचिवालय पूल में आवास के आवंटन के लिए पात्र नहीं है और/या इसके विपर्ययेन।

## 26. आवास का विवेकाधीन आवंटन-

लोक सभा सचिवालय के सेवारत अधिकारियों को विवेकाधीन आवंटन की अनुमति केवल चिकित्सा और कार्यात्मक आधार पर दी जाएगी। चिकित्सा और कार्यात्मक आधार के लिए आवास का विवेकाधीन आवंटन लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाएगा।

## 27. लोक सभा सचिवालय पूल के आवासों और सामान्य पूल के रिहायशी आवासों का अंतर-पूल आदान-प्रदान-

आवासों का अंतर-पूल हस्तांतरण लोक सभा सचिवालय और संपदा निदेशालय की आपसी सहमति से किया जा सकेगा।

## 28. आवास के आवंटन का अभ्यर्पण -

- (1) कोई आवंटिती, आवंटन की अवधि के दौरान किसी भी समय पर आवास के आवंटन का अभ्यर्पण कर सकेगा।
- (2) यदि कोई आवंटिती, आवास का अभ्यर्पण करता है, तो अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उसे आवास का आवंटन करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 29. आवंटिती द्वारा आवास का अनुरक्षण -

- (1) आवंटिती, जिसे रिहायशी आवास का आवंटन किया गया है, आवास और परिसर को स्वच्छ स्थिति में रखेगा और ऐसा आवंटिती सरकार द्वारा या उसके अनुरक्षण अभिकरणों द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे नहीं उगाएगा और न ही अनुरक्षण अभिकरणों से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, आवास से लगे किसी बगीचे, आंगन या परिसर में विद्यमान किसी पेड़ या झाड़ी को काटेगा या उसकी छंटाई करेगा।
- (2) सम्बन्धित अनुरक्षण अभिकरण, इस नियम का उल्लंघन करके उगाए गए वृक्ष, बागान या वनस्पति को सम्बन्धित आवंटिती के खर्चे और जोखिम पर हटा सकेंगे।

## 30. आवंटिती द्वारा मरम्मत कार्य करने के लिए अनुरक्षण अभिकरणों के साथ सहयोग -

- (1) आवास के सभी आवंटिती, सरकारी कॉलोनियों में सभी प्रकार के मरम्मत और नवीकरण कार्य कार्य करने के लिए रिहायशी आवास के संबन्धित अनुरक्षण अभिकरणों के साथ सहयोग करेंगे।
- (2) यदि अनुरक्षण अभिकरण से किसी आवंटिती के विरुद्ध असहयोग की शिकायत प्राप्त होती है, तो लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और इन नियमों के अनुसार उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

## 31. व्यापार या कारबार या किसी अन्य अप्राधिकृत कार्यकलाप के लिए आवास का दुरुपयोग-

- (1) इन नियमों के अनुसार आवंटिती या अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आवास का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
- (2) आवंटित आवास का अप्राधिकृत उपयोग करने के लिए आवंटिती के विरुद्ध इन नियमों के अनुसार और इस सम्बन्ध में समय-समय पर लोक सभा सचिवालय/संपदा निदेशालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

## 32. जन उपयोगी सेवाओं के लिए अपेक्षित प्रभार या शुल्क का भुगतान -

- (1) आवास के आवंटिती सभी जन उपयोगी सेवाओं जैसे विद्युत, जल, गैस आदि के बिल की प्राप्ति पर नियमित रूप से ऐसे प्रभार और शुल्क का भुगतान करेंगे।
- (2) यदि आवंटिती ने आवास के अभ्यर्पण या उसे खाली करने से पहले जन उपयोगी सेवाओं के लिए संबंधित प्राधिकारियों को देय धनराशि का भुगतान नहीं किया है तो अनुरक्षण अभिकरण द्वारा आवास का अभ्यर्पण या उसकी रिक्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी।

## 33. सरकारी कॉलोनियों में अप्राधिकृत निर्माण-

- (1) सरकारी रिहायशी कॉलोनियों में कोई अप्राधिकृत निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई अप्राधिकृत निर्माण किया गया है तो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971(1971 का 40) के

अधीन अधिसूचित संपदा अधिकारी या संबंधित अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, उसे हटा दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा।

(2) यदि उसी आवंटिती के आवास में कोई और अप्राधिकृत निर्माण पाया जाता है तो ऐसे आवंटिती को उपलब्ध कराए गए आवास के आवंटन को उसके निरीक्षण की तारीख से रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में सेवा की शेष अवधि के लिए उसे आवास के आवंटन हेतु विवर्जित कर दिया जाएगा।

(3) आवास या लोक परिसर में अप्राधिकृत निर्माण या अतिक्रमण से सम्बंधित मामलों के निपटान की प्रक्रिया और सम्बंधित अनुरक्षण अभिकरणों के उत्तरदायित्व, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

#### 34. आवंटन रद्द होने के पश्चात अप्राधिकृत अधिभोग-

इन नियमों के किसी उपबंधों के अधीन किसी आवास के आवंटन को रद्द कर दिये जाने या रद्द मान लिए जाने के पश्चात, यदि आवास, आवंटिती, या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में रहता या अधिभोग में रह चुका है, तो ऐसा आवंटिती आवास, सेवाओं, फर्नीचर, बगीचे के अधिभोग और उनके उपयोग के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गए प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

#### 35. रिक्ति नोटिस जारी किया जाना और आवंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना -

(1) आवास के सभी आवंटितियों या उनके परिवारों को प्रतिधारण की अनुज्ञेय अवधि की समाप्ति से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व रिक्ति नोटिस जारी किया जाएगा।

(2) जहां आवंटितियों द्वारा प्रतिधारण की अनुज्ञेय अवधि की समाप्ति के पश्चात् क्वार्टरों को रिक्त नहीं किया गया है तो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के अधीन संबंधित प्राधिकारी ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

#### 36. ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जो आवास के अस्थायी आवंटन की अवधि समाप्त होने पर आवास रिक्त करने में विफल रहते हैं -

(1) विवाह या अन्य सामाजिक प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से आवंटित आवास आवंटन की अवधि की समाप्ति पर रिक्त कर दिया जाएगा।

(2) आवंटित आवास को रिक्त न किए जाने की स्थिति में ऐसे मामले को, अप्राधिकृत अधिभोगी के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए संपदा अधिकारी के पास भेजा जाएगा और ऐसे अप्राधिकृत अधिभोग के लिए हर्जाना वसूला जाएगा।

#### 37. आवास की उप-किरायेदारी-

(1) आवंटिती उसको आवंटित आवास में अपने परिवार और निकटतम संबंधियों के साथ रहेगा/रहेगी।

(2) न्यायालय के किसी आदेश द्वारा किसी संबंध के न बने रहने के मामले में, ऐसा संबंधी आवंटिती के साथ नहीं रहेगा।

(3) नौकर आवास गृह, आउट हाउस और गैराज केवल प्रामाणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा सकेंगे।

(4) आवंटिती, जो आवास में अपने परिवार या निकटतम संबंधियों के साथ रहता/रहती है, लोक सभा सचिवालय को अपने परिवार या उसको आवंटित आवास में रहने वाले निकटतम संबंधियों के पूरे विवरण देते हुए, पूर्व सूचना देगा;

परंतु ऐसे अतिथियों के विवरण, जो आवास में पन्द्रह दिन से अधिक अवधि के लिए ठहरने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति के सम्पूर्ण विवरण देते हुए, लोक सभा सचिवालय को सूचना देगा/देगी।

(5) यदि कोई अधिकारी, जिसे आवास आवंटित किया गया है, अनधिकृत रूप से आवास को किराए पर देता है या हिस्सेदार से किराया वसूल करता है या आवास के किसी भी हिस्से में कोई अनधिकृत संरचना खड़ी करता है या आवास या उसके किसी भाग का प्रयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उसके निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न है या विद्युत कनेक्शन या जल कनेक्शन के साथ छेड़-छाड़ करता है या इन नियमों को भंग करता है या आवंटन के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करता है या आवास या परिसरों का प्रयोग, किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है या करने की अनुमति देता है या होने देता है जो संपदा अधिकारी के विचार में अनुचित है या ऐसा आचरण करता है जो संपदा अधिकारी की राय में उनके पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की दृष्टि से अनुचित हो या आवंटन प्राप्त करने के लिए किए गए किसी

आवेदन में या लिखित कथन में जान-बूझकर गलत जानकारी देता है, ऐसी स्थिति में सम्पदा अधिकारी, आवंटिती के विरुद्ध किसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आवास का आवंटन रद्द कर सकेगा:

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में, पद “आवंटिती” से, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके परिवार का कोई सदस्य और आवंटिती के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति, भी शामिल है।

(6) यदि कोई अधिकारी इन नियमों के उल्लंघन में, उसको आवंटित आवास या उसके किसी भाग या किसी आउट हाउस या गैराज को उप-किरायेदारी पर देता है, तो उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे नियमानुसार बढ़ा हुआ अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाएगा। प्रत्येक मामले में वसूल किए जाने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क की मात्रा और वह अवधि जिसके लिए उसे वसूल किया जाएगा, का निर्धारण संपदा अधिकारी द्वारा मामले के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिकारी को भविष्य में संपदा अधिकारी द्वारा यथाविनिर्णीत निर्दिष्ट अवधि के लिए आवास साझा करने से विवर्जित किया जा सकेगा।

(7) जहां किसी परिसर की अप्राधिकृत उप-किरायेदारी के कारण आवंटन को रद्द करने की कार्यवाई की जाती है, वहां आवंटिती और उसके साथ रहने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को परिसर खाली करने के लिए साठ दिन की अवधि दी जाएगी। आवंटन परिसर खाली करने की तारीख से या आवंटन रद्द करने के आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति, जो भी पहले हो, से रद्द कर दिया जाएगा।

(8) सम्पदा अधिकारी इस नियम के उप-नियम (5) से (7) के तहत कोई एक कार्यवाई या सभी कार्यवाइयां करने के लिए सक्षम होगा और उन नियमों या उसे दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी को रिहायशी आवास के आवंटन के लिए तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपात्र घोषित करने में सक्षम होगा।

(9) जहां इस नियम के तहत संपदा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित की जाती है, पीड़ित व्यक्ति उसके द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर संपदा अधिकारी के माध्यम से लोक सभा सचिवालय के महासचिव के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(10) लोक सभा सचिवालय निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा, अर्थात्:-

(क) इस नियम के अधीन उपबंधित सभी या कोई एक कार्यवाई करने के लिए;

(ख) आवंटिती को उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए रिहायशी आवास के आवंटन के लिए अपात्र घोषित करने के लिए;

(11) उप-किरायेदारी का निरीक्षण करने के प्राधिकृत पदधारी द्वारा निरीक्षण के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो सम्पदा निदेशालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

(12) उप-किरायेदारी का संदेह होने के मामले में आवास के आवंटन को रद्द करने या अन्यथा का विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस सम्बन्ध में आवंटिती को समान अवसर उपलब्ध कराके जांच के पश्चात किया जाएगा।

### 38. आवास के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान-

(1) लोक सभा पूल के आवास के आवंटन के लिए आवंटितियों पर या अन्य अपात्र अधिकारी या संगठन पर प्रभारित किए जाने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क की दरें, समय-समय पर सरकार/लोक सभा सचिवालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार होगी।

(2) जहां आवास का आवंटन या वैकल्पिक आवास स्वीकार कर लिया गया है, अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान का दायित्व आवास के भौतिक अधिभोग की तारीख से प्रारंभ होगा।

(3) कोई आवंटिती, जो स्वीकृति के पश्चात् प्राधिकार पत्र की प्राप्ति की तारीख से पाँच कार्यदिवस के भीतर उस आवास का कब्जा लेने में विफल रहता है, पर आवंटन की तारीख से एक मास का अनुज्ञप्ति शुल्क भरित किया जाएगा:

परंतु यह उपबंध उस मामले में लागू नहीं होगा जब अनुरक्षण अभिकरण विहित अवधि के भीतर रहने लायक स्थिति में आवास पर कब्जा नहीं देता है या किसी अन्य कारण से आवास भौतिक अधिभोग के लिए तैयार नहीं है।

(4) आवंटिती, जिसे कोई आवास आवंटित किया गया है, उस अवधि के दौरान, जिसके लिए आवास आवंटित किया गया है और उसे आवंटित रहता है या इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन जहां आवंटन रद्द कर दिया गया है, आवास और

उससे संलग्न आउट हाउस के पूर्णतः रिक्त होने तक और उसका पूर्णतः रिक्त कब्जा लोक सभा सचिवालय को प्रत्यावर्तित होने तक अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान और आवास में हुई वाजिब टूट-फूट को छोड़कर किसी नुकसान के लिए या फर्नीचर, फिक्सचर या फिटिंग या सरकार द्वारा उसमें उपलब्ध कराई गई सेवाओं की किसी प्रकार की क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से भुगतान का दायी होगा/होगी।

(5) अप्राधिकृत अधिभोग या उप-किरायेदारी या आवास, नौकर आवास-गृह या गैराज के दुरुपयोग के लिए हर्जाने की दर, लोक सभा सचिवालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(6) आवास के सभी आवंटिती उनको आवंटित आवास के प्रतिधारण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप में करेंगे।

(7) ऐसे मामले में जहां कोई आवंटिती, जिसे कोई आवास आवंटित किया गया है, स्थायी या अर्ध-स्थायी सरकारी सेवक नहीं है, वह अनुज्ञप्ति शुल्क के यथासमय भुगतान के लिए और ऐसे आवास के सम्बन्ध में और बदले में उपलब्ध कराए गए किसी अन्य आवास के लिए उसके द्वारा देय किसी अन्य प्रभार के भुगतान के लिए, लोक सभा सचिवालय द्वारा इसके लिए विहित प्ररूप में, एक प्रतिभू, जो लोक सभा सचिवालय का स्थायी अधिकारी होगा, द्वारा प्रतिभूति बन्धपत्र का निष्पादन कराएगा।

(8) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में बना नहीं रहता/रहती है या दिवालिया हो जाता/जाती है या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं हो सकता/सकती है तो आवंटिती ऐसे तथ्य या घटना की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर नया बंधपत्र दूसरे प्रतिभू द्वारा निष्पादित कराके देगा/देगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता/रहती है तो उसके आवास का आवंटन, जब तक लोक सभा के महासचिव द्वारा अन्यथा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता, उस घटना की तारीख से रद्द हुआ समझा जाएगा।

### 39. इन नियमों से पहले किए गए आवंटन को जारी रखना-

किसी निवास का कोई भी वैध आवंटन जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू नियमों के तहत विद्यमान है, इन नियमों के तहत विधिवत किया गया आवंटन माना जाएगा, भले ही जिस अधिकारी को यह आवंटित किया गया है वह नियम के अंतर्गत इस टाइप के निवास का हकदार नहीं है, और इन नियमों के सभी प्रावधान, उस आवंटन और उस अधिकारी के संबंध में तदनुसार लागू होंगे।

### 40. स्पष्टीकरण

यदि इन नियमों के स्पष्टीकरण के संबंध में कोई प्रश्न उठाया जाता है तो इस पर निर्णय के लिए इसे लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा।

### 41. नियमों में छूट का अधिकार

अध्यक्ष किसी अधिकारी या आवास या अधिकारियों की श्रेणी या आवास के टाइप के मामले में इन सभी नियमों या इनके किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

### 42. प्रत्यायोजन

लोक सभा के महासचिव समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि इन नियमों के तहत उनके द्वारा प्रयोज्य कोई भी शक्ति (इस नियम के तहत शक्तियों के अलावा) आदेश में यथानिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन लोक सभा सचिवालय के ऐसे अधिकारी, जिसे आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, द्वारा भी प्रयोज्य हो सकती है।

[फा. सं. 022/1/2022/213952]

सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव

**अधिसूचना:** मूल नियम दिनांक 1 मई 1974 की संख्या जी.एस. आर. 576 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नलिखित क्रमांक के माध्यम से संशोधन किया गया है :

1	दिनांक 17 जून, 1977 का जी.एस. आर. 279(ई),
2	दिनांक 1 दिसंबर, 1978 का जी.एस. आर. 566(ई)
3	दिनांक 7 जुलाई, 1979 का जी.एस. आर. 439 (ई)



4	दिनांक 26 सितंबर, 1986 का जी.एस. आर.1110 (ई)
5	दिनांक 22 दिसंबर, 1987 का जी.एस. आर.1011 (ई)
6	दिनांक 1 जनवरी, 1997 का जी.एस. आर.3(ई)
7	दिनांक 6 फरवरी, 1997 का जी.एस. आर.67(ई)
8	दिनांक 20 मार्च, 1998 का जी.एस. आर.142(ई)
9	दिनांक 6 मई, 1998 का जी.एस. आर.247(ई)
10	दिनांक 14 अक्तूबर, 1998 का जी.एस. आर.621(ई)
11	दिनांक 8 फरवरी, 1999 का जी.एस. आर.81(ई)
12	दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 का जी.एस. आर.742(ई)
13	दिनांक 3 मई, 2009 का जी.एस. आर.314(ई)
14	दिनांक 26 दिसंबर, 2013 का जी.एस. आर.799(ई)
15	दिनांक 20 फरवरी, 2017 का जी.एस. आर.259(ई)

## LOK SABHA SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2023

**G.S.R. 850(E).**—In exercise of the powers conferred by the Rule 45 of Fundamental Rules, as made applicable to the Officers of the Lok Sabha Secretariat by Recruitment and Conditions of Service Order No. 185 dated the 19<sup>th</sup> December, 1957 and in supersession of the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974, the Speaker of the Lok Sabha hereby makes the following rules regulating the allotment of accommodation to Lok Sabha Secretariat employees under the control of the Lok Sabha Secretariat, namely:-

#### 1. Short title and commencement-

- (1) These Rules may be called the Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions-

In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "accommodation" means the Lok Sabha Secretariat Pool Residential Accommodation under the control of Lok Sabha Secretariat;
- (b) "allotment" means the grant of a licence to occupy a residential accommodation in accordance with the provisions of these rules and include allotment by Automated System of Allotment (ASA) or by manual system of allotment;
- (c) "allotment of garage" means the grant of a licence to occupy a garage in accordance with the provisions of these rules;
- (d) "damages" means a compensation to be levied in multiples of licence fee in the event of unauthorized occupation or subletting or misuse of whole or any part of accommodation or garages by the occupant of the accommodation or garages;
- (e) "Lok Sabha Secretariat" means Office of the Lok Sabha Secretariat;
- (f) "Lok Sabha Secretariat Pool of Residence" means all the residences presently under the administrative control of Lok Sabha Secretariat;
- (g) "Officer" means a person appointed to, or borne on the cadre of the Secretarial staff of the Lok Sabha;
- (h) "eligible type of accommodation" in relation to an officer means the type of accommodation to which he is eligible under these rules;
- (i) "employee" means an employee of the Lok Sabha Secretariat;
- (j) "family" means the wife or husband of allottee, as the case may be, and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the allottee;
- (k) "guest" means a casual visitor staying temporarily with the allottee;

- (l) "own house" means a building or part thereof meant for residential purposes and owned by the allottee or by any member of his/her family;
- (m) "immediate relations" mean relationship such as Grandfather, Grandmother, Grandsons, Granddaughters, Father-in-law, Mother-in-law, Son-in-law, Daughter-in-law and include relationship established by legal adoption;
- (n) "licence fee" means a fee payable monthly in respect of the accommodation allotted under these rules;
- (o) "misuse", in relation to an allotment, means an accommodation or a servant quarter or a garage being used by allottee himself/herself or by his/her family members or immediate relations staying with him/her for the purpose other than the purposes provided under these rules;
- (p) "subletting" means letting out of a Lok Sabha Secretariat Pool Residential Accommodation partly or wholly by an allottee to any person outside allottee's family and immediate relations;
- (q) "surrender of accommodation" means vacation of accommodation after physical occupation of the accommodation by the allottee on his/her own volition during the allotment period;
- (r) "transfer" means a transfer from an eligible officer to an ineligible officer and includes deputation to a post in an ineligible officer or an organisation.

### 3. Eligible zone for accommodation-

All Lok Sabha Secretariat (LSS) employees (except who are in deputation/contract/co-terminus basis in Lok Sabha Secretariat) who fulfill the conditions of eligibility under these rules and have been specifically declared to be eligible for allotment of accommodation by the Lok Sabha Secretariat shall be eligible for allotment or retention of accommodation from the LSS Pool.

### 4. Entitlement/Classification for/of types of accommodation-

- (1) Save as otherwise provided by these rules, an Officer/Official will be eligible for allotment of residence of the type shown in the Table below:-

Type of Residences	Existing Grade Pay	Pay Level in the Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission)
I	Rs. 1900	2
II	Rs. 2000, Rs. 2200, Rs. 2400 and Rs. 2800	3,4,5
III	Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800	6,7,8
IV	Rs. 5400 to Rs. 6600	10,11
VA (DII)	Rs. 7600 and Rs. 8000	12
VB (DI)	Rs. 8700 and Rs. 8900	13
VIA (CII)	Rs. 10,000	14
VIB (CI)	Rs. 67000 to Rs. 74999	15 (Index numbers 1 to 4 in the level)
VII	Rs. 75000 to 79999	15 (Index numbers 5 to 8 in the level), 16
VIII	Rs. 80000 and above	17, 18

- (2) The calculation of date of priority and preparation of waiting lists for different types of accommodations shall be as under:

- (a) The date of priority in respect of type I to type IV accommodation shall be determined on the basis of the date of joining of the employee in the Lok Sabha Secretariat Service and the eligibility for the type of accommodation shall be decided as per the level of the applicant in the pay matrix:
- Provided that an applicant under this category shall be allowed to bid for one type lower accommodation than the eligible type.
- (b) The *inter-se* seniority in respect of type I to type IV accommodation shall be considered on the basis of the following factors, namely:-
- (i) where the date of joining the Lok Sabha Secretariat Service of two or more applicants is the same, the applicant having a higher level pay in the level shall be senior in the waiting list; and
- (ii) where the date of joining the Lok Sabha Secretariat and pay in the level of two or more applicants are the same, the applicant retiring earlier may be accorded priority over the applicant retiring later.

- (c) The date of priority in respect of type VA and above accommodation shall be determined on the basis of the date from which the applicant is continuously drawing relevant pay in the Pay Matrix in the Lok Sabha Secretariat.
- (d) The *inter-se* seniority for the type VA and above accommodation shall be considered on the basis of the following factors, namely:-
- (i) where the priority date of two or more applicants is the same, the applicant having a higher level pay in the level shall be senior in the waiting list;
  - (ii) where the date of priority and the pay in the level of two or more applicants are the same, the applicant who has joined the Lok Sabha Secretariat Service earlier shall be senior in the waiting list; and
  - (iii) where the date of priority, pay in the level and the date of joining the Lok Sabha Secretariat Service of two or more applicants are the same, the applicant retiring earlier may be accorded priority over the applicant retiring later.
- (3) The applicants entitled for type V and above accommodation shall also be eligible to apply for accommodation below their entitlement subject to the condition that such accommodation shall not be below Type IV accommodation.
- (4) The benefit of previous services in the defence forces or any other organization will not be given for the purposes of calculation of date of priority.
- (5) Personal pay shall not be considered for the purposes of determining the *inter-se* seniority in the waiting list.
- (6) Non-practising Allowance, Military Service Pay or any other such component of pay shall not be considered for the purposes of determining the *inter-se* seniority in the waiting list.

#### **5. Application for accommodation-**

- (1) Eligible employees of Lok Sabha Secretariat may submit an online application on Lok Sabha Secretariat Intranet for allotment of accommodation to which he/she is eligible under these rules and the entitled type of accommodation shall be offered as per the priority in accordance with these rules having regard to the allottee's preference.
- (2) Applications received prior to the specified bidding date shall be included in the respective unified waiting list and considered for allotment in the next bidding cycle subject to fulfillment of terms and conditions for allotment as per these rules.
- (3) The applicant shall furnish various particulars in online application form which shall be verified by the designated Officer and in case of any discrepancy in the application or furnishing of incorrect information in the application, the applicant and the Verifying Officer shall be liable for furnishing of incorrect information and disciplinary action shall be taken against them including cancellation of allotment of accommodation if allotment was made based on incorrect information.
- (4) No application shall be entertained for accommodation within six months of the date of superannuation.

#### **6. Preparation of waiting lists for various types of accommodation-**

- (1) A unified waiting list shall be prepared for each type of accommodation except for Type VII and Type VIII accommodation.
- (2) A unified waiting list shall have names of the applicants either applying or who have applied for initial as well as for change of accommodation and shall be prepared as per the entitlement for a type of accommodation.
- (3) The names of applicants entitled for Type V and above accommodation shall be included in all unified waiting lists of below types of accommodation for which they are eligible.
- (4) The names of applicants entitled for Types II, III and IV accommodation shall be included in all unified waiting lists of one type below accommodation for which they are eligible.

#### **7. Deletion of names of non-serious applicants from Unified Waiting Lists-**

The names of applicants, who have neither updated their personal data nor opted for any accommodation during the past one year, shall be automatically deleted from the unified waiting list:

Provided that the applicant whose name is deleted may get his/her name activated again by filing the prescribed form online and such applicant shall be considered in the unified waiting list of the respective type of accommodation.

**8. Offer of allotment of accommodation-**

- (1) Save as otherwise provided in these rules, accommodation falling vacant in all types will be allotted by Automated System of Allotment (ASA) to the applicant applying for initial allotment or for change of accommodation from the unified waiting list for that type of accommodation under these rules.
- (2) The Lok Sabha Secretariat may, in emergent circumstances where the accommodation in occupation of the allottee is required to be vacated, allot him/her an alternate accommodation of the same type of accommodation or the type next below the type of accommodation in occupation of the allottee, subject to availability.

**9. Period for which allotment subsists-**

An allotment shall be effective from the date on which it is accepted by the allottee and shall continue till in the Lok Sabha Secretariat service or in force until:

- (a) the expiry of the concessional period permissible under these rules after the allottee ceases to be on duty in Lok Sabha Secretariat;
- (b) it is cancelled by the Lok Sabha Secretariat/Estate Officer or is deemed to have been cancelled under any provisions in these rules;
- (c) it is surrendered by the allottee;
- (d) the allottee ceases to occupy the accommodation.

**10. Acceptance of allotment-**

An offer of allotment of an accommodation shall be accepted by the allottee within eight days from the date of allotment of the accommodation through Automated System or by manual system of allotment, as the case may be.

**11. Process after acceptance-**

- (1) After acceptance of the allotted accommodation, the allottee shall take physical possession of the accommodation from the CPWD or from any other maintenance agency, as the case may be, within five working days from the date of receipt of the acceptance letter and the CPWD or any other maintenance agency, as the case may be, shall hand over the allotted accommodation to the allottee.
- (2) In case the allotted accommodation is not ready for immediate occupation, CPWD or any other maintenance agency shall issue a Technical Occupation Report to the allottee on receipt of authority letter from the Lok Sabha Secretariat.
- (3) The CPWD shall issue a Physical Occupation Report to the allottee once the accommodation is ready for occupation and after handing over the accommodation to the allottee in habitable condition.

**12. Non-acceptance of offer of allotment or failure to occupy the allotted accommodation after acceptance-**

- (1) If any allottee fails to accept the allotment of a residential accommodation within eight days from the date of allotment of the said accommodation, or fails to take possession of that accommodation within five working days from the date of receipt of the letter of authorisation, he/she shall be debarred to apply for accommodation for a period of three months from the date of non-acceptance of allotment subject to payment of one month's normal licence fee for that type of accommodation.
- (2) The date of non-acceptance of allotment shall be calculated from the date of allotment.
- (3) If an allottee occupying a lower type of accommodation refuses to accept the offer of an accommodation of the type for which he is eligible under these rules, he/she shall be permitted to continue in the previously allotted accommodation:

Provided that such allottee shall not be eligible for another allotment for a period of six months from the date of non-acceptance of such allotment.

**13. Allotment of accommodation on Unsafe or Dangerous grounds-**

- (1) An allottee, whose residential accommodation is unsafe or dangerous may make an application to the concerned maintenance agency to declare such accommodation as unsafe or dangerous for living and an officer not below the rank of an Executive Engineer, CPWD or equivalent officer in any other maintenance agency on satisfying himself/herself that the accommodation concerned is unsafe or dangerous, issue a certificate of declaration to the effect, to the Lok Sabha Secretariat in writing and enter the accommodation in the Unsafe Accommodation Register.
- (2) Allotment of alternate accommodation to an allottee on declaration of a house as unsafe or dangerous shall be done through Automated System of Allotment or manual system of allotment as may be applicable.

(3) In cases where an individual house in a Government residential colony is declared as unsafe or dangerous, an alternate allotment of same type of accommodation is to be made on priority on the following basis:

- (a) Vacancies in the same locality or nearby locality to be identified for allotment where such occupants would be given priority in the same type of accommodation over the unified (change/initial) waiting list;
- (b) The allottee in occupation of a specific floor may apply for that floor and above accommodation Type only and allotment will be made accordingly;
- (c) Equal number of identified vacancies will be placed for allotment in ASA in relation to the number of such unsafe or dangerous houses.

#### 14. Eligibility of allottees married to each other-

(1) No employee of the Lok Sabha Secretariat shall be allotted an accommodation under these rules if the spouse of such Government Servant has already been allotted an accommodation, unless such accommodation is surrendered:

Provided that this sub-rule shall not apply where the wife and husband are residing separately in pursuance of –

- (i) an order of judicial separation made by any Court; or
- (ii) an order to proceed to frame and record the issues for settlement of the proceedings by any Court in which a petition filed by either spouse for dissolution of marriage by a decree of divorce is pending and either of them has furnished an undertaking to surrender the accommodation allotted to her or him/her forthwith in case of revival of conjugal rights with her or his spouse.

(2) Where two allottees in occupation of separate accommodation allotted under these rules marry each other, they shall within one month of marriage, surrender one of the accommodations.

(3) If one of the accommodations is not surrendered within the stipulated period as required by sub-rule (2), the allotment of the accommodation of the lower type shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period and if the accommodations are of the same type, the allotment of such one of them as the Lok Sabha Secretariat may decide, shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

(4) Where both husband and wife are employed in Lok Sabha Secretariat, the title of each of them to allotment of an accommodation under these rules shall be considered independently.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4), (i) if a wife or husband, as the case may be, who is an allottee of an accommodation under these rules, is subsequently allotted a residential accommodation from General Pool or other Government Office, she or he shall surrender anyone of the accommodation within one month of such allotment:

Provided that this clause shall not apply where the husband and wife are residing separately in pursuance of an order of judicial separation made by any Court. (ii) where two allottees, in occupation of separate accommodations, one allotted under these rules and another from General Pool or other Government Office, marry each other, anyone of them shall surrender anyone of the accommodation within one month of such marriage.

(6) If an accommodation is not surrendered as required under sub-rule (5), the allotment of the accommodation in the Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been cancelled on the expiry of such period.

#### 15. Allotment to Women Employees (Ladies Pool)-

(1) The allotment under Ladies Pool Quota will be made from Type I to Type VA only. Separate Unified Waiting Lists for Type I to VA accommodation shall be prepared for the Lady Employees.

(2) 10% of vacancies arising in Type I to Type VA accommodation of Lok Sabha Secretariat Pool in the ratio of 1:2 i.e., Single women and Married women, respectively will be reserved for Lady Employees.

Explanation-For the purposes of this rule- (i) "Married lady employee" means a lady employee whose marriage is subsisting and who is not judicially separated from her husband; and (ii) "Single Lady employee" means an unmarried lady employee and include a widow with or without children.

(3) The *inter-se* seniority of the lady employees eligible for allotment of accommodation under this rule shall be determined as per rule.

(4) All Lady Employees, who are otherwise eligible for LSS Pool accommodation, will also be eligible for allotment from the Ladies Pool.

(5) Lady employees, who are already in occupation of accommodation, will be eligible for allotment of higher type of accommodation or change in the same type, in their own turn, from the Ladies Pool and from General Pool.

(6) If the allotment to be made to Lady Employees clashes with allotment of accommodation to SC/ST employees under reserved quota, the accommodation will be first allotted to SC/ST employees and then to ladies quota.

(7) A Lady employee who had been debarred from Lok Sabha Secretariat Pool of accommodation for non-acceptance of offer of allotment from general quota will not be considered for allotment from reserve quota during her debarred period and vice-versa.

(8) If no Single Lady Employee is eligible for allotment, the quota reserved for them may be allotted to the married lady employee and vice-versa.

**16. Reservation in allotment to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees-**

(1) The reservation in allotment of accommodation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees shall be ten per cent (10%) in Type I and Type II accommodation and five per cent (5%) in Type III and IV accommodation.

(2) The allotment from Type I to IV shall be made in the ratio of 2: 1 vacancies to Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, respectively.

(3) Separate unified waiting lists for Type I to IV accommodation shall be prepared for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees.

(4) In case, there is no Scheduled Tribes applicant in the unified waiting list, the quota reserved for the Scheduled Tribes may be allotted to a Scheduled Castes applicant and vice versa.

(5) Scheduled Castes and Scheduled Tribes applicants, who are already in occupation of Lok Sabha Secretariat Pool accommodation, shall be eligible for allotment of higher type of accommodation from the quota reserved for them under this rule.

(6) In respect of Types I and II accommodation, there will be a 60 point roster system and the vacancies at point number 10, 20, 40 and 50 shall be allotted to Scheduled Castes applicants and the vacancies at point number 30 and 60 shall be allotted to Scheduled Tribe applicants.

(7) In respect of Type III and IV accommodation, there will be a 60 point roster system and the vacancies at point number 20 and 40 shall be allotted to Scheduled Caste applicants and vacancy at point number 60 shall be allotted to Scheduled Tribe applicants.

(8) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes applicants shall also be eligible for allotment from the general pool.

(9) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes applicants who had been debarred from Lok Sabha Secretariat Pool of accommodation for non-acceptance of offer of allotment from general quota will not be considered for allotment from reserve quota during their debarred period and vice-versa.

(10) The Scheduled Caste and Scheduled Tribe applicants shall mention the fact that as to whether they belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe in their application for allotment of accommodation, which shall be verified by the designated Officer from their records at the time of acceptance of allotment of the accommodation by the applicant.

**17. Allotment of surplus accommodation-**

In case of availability of surplus accommodation in any type, an applicant may be allotted an accommodation lower than the entitled type on payment of normal licence fee of his/her allotted type.

**18. Temporary allotment of accommodation for marriage or social functions-**

The temporary allotment of accommodation (if available) for marriage or social purposes shall be allotted as per guidelines issued by the Lok Sabha Secretariat.

**19. Concessional period of retention of accommodation-**

The allottee may, subject to the conditions laid down in these rules, be permitted to retain the accommodation on the happening of any of the events specified in column (2) of the table below, for the period specified in the corresponding entry in column (3) thereof, provided that the accommodation is required for the bonafide use of the allottee or members of his/her family:

Sl. No.	Events	Permissible period of retention of accommodation
(1)	(2)	(3)
1	Resignation, dismissal or removal from Service, termination of service or unauthorised absence without permission, compulsory retirement under [CCS (CCA) Rules, 1965] and for non-regular Government servants.	one month on normal licence fee
2	Retirement, voluntary retirement, retirement on medical grounds, terminal leave or compulsory retirement [under on normal licence fee FR 56(j)], retirement on deputation from ineligible organisations during the initial constitution of such organisation, technical resignation, death of allottee on reemployment (irrespective of retention availed on retirement) and death of an allottee who is not a regular Government servant or deputation outside India.	six months on normal licence fee
3	Transfer to a place outside from the existing place, transfer to an ineligible office, on proceeding on foreign service in India, temporary transfer in India or transfer to a place outside India or deputation within India.	Two months on normal licence fee plus six months on double licence fee.
4	To eligible spouse or ward in case of death of the allottee	Twelve months on normal licence fee and for a further period of twelve months on normal licence fee provided the deceased or any member of the family does not own a house in Delhi/NCR.
5	Study leave outside India	For the period of leave but not exceeding six months
6	Study leave in India	For the period of leave but not exceeding six months
7	Leave on medical grounds	For the full period of leave

## 20. Change of accommodation in same type or entitled higher type of accommodation-

- (1) An allottee to whom an accommodation has been allotted under these rules may apply for a change to another same type of accommodation only after taking physical possession of accommodation allotted under initial allotment.
- (2) Only one change shall be allowed in the same type of accommodation to the allottee.
- (3) An allottee, who intends to change the accommodation already allotted to him/her shall make an application in the form specified by Lok Sabha Secretariat, and thereafter, the name of such allottee shall be included in the concerned type unified waiting list.
- (4) The date of priority or the inter-se seniority of the allottees in the waiting list for change of accommodation in respect of Type I to Type VIB shall be as applicable to initial allotment.
- (5) The change of same type of accommodation shall be offered as per the priority in accordance with these rules and having regard to the allottee's preference:

Provided that no change in the same type of accommodation shall be allowed to an allottee within six months of the date of superannuation.

- (6) If an allottee fails to accept a change of accommodation offered to him/her within eight days of issue of such offer or allotment, he/she shall not be considered again for a change of accommodation for one year from the date of non-acceptance for that type of accommodation.
- (7) An allottee who, after accepting a change of accommodation fails to take possession of the same, shall be charged one month licence fee for such accommodation in accordance with the provisions of these rules in addition to the normal licence fee for the accommodation already in his/her possession the allotment of which shall continue to subsist:

Provided that if CPWD fails to make the accommodation offered on change habitable within the prescribed time period, a certificate from the concerned Executive Engineer shall be furnished in this regard by CPWD and allottees will be exempted from payment of licence fee for the intervening period in such cases.

(8) Where an allottee, who is in occupation of an accommodation, is allotted another accommodation and he/she occupies the new accommodation, the allotment of former accommodation shall be deemed to have been cancelled from the date of physical occupation of the new accommodation:

Provided that such date of occupation, the allottee may, retain the former accommodation on payment of normal licence fee for a period of thirty days for shifting to the newly allotted accommodation:

Provided further that if the previous accommodation is not vacated within a period of thirty days, the allottee shall be liable to pay damages for use and occupation of the previous accommodation, furniture and garden charges as may be determined by the Government from time to time with effect from the 31<sup>st</sup> day from the date of physical occupation of the new accommodation and the accommodation slotted in the change shall be deemed to have been cancelled under these rules.

(9) The allottee shall ensure before applying for change of accommodation that he continues to be entitled for that type of accommodation on the basis of revised entitlement as well as other conditions governing such change of accommodation and the respective allotment authority or estate office shall verify this fact before accepting the prescribed acceptance form of the applicant.

(10) No change of accommodation shall be allowed to an allottee under this rule if an enquiry is under progress against the allottee on the charge of subletting.

#### **21. Change of accommodation in the event of death of a member of family-**

Notwithstanding anything contained in these rules, an allottee may be allowed a change of accommodation on the death of any member of his/her family if he applies for a change within six months of such occurrence, provided that the change will be given in the same type of accommodation, same floor and in the same area as the accommodation already allotted to the allottee.

#### **22. Shifting of allottees in case of quarrel between neighbours-**

(1) Any complaint relating to quarrel between neighbours in Government colonies shall be examined in detail by the Superintending Engineer (Civil), CPWD looking after maintenance of accommodation, who shall then make his/her recommendations to the Lok Sabha Secretariat.

(2) The allottee found guilty under this rule shall be shifted to another accommodation in the same locality but at a distance from the accommodation of the allottee with whom she/he had picked up quarrel, or to another nearby or remote locality, depending upon the nature of the offence or situation.

(3) If the allottee so shifted to another place again picks up quarrel with his/her neighbours, his/her allotment shall be cancelled and he shall be debarred from allotment of accommodation for a period varying from one year to two years depending upon the nature of the offence:

Provided that if the allottee who is debarred under this sub-rule, on subsequent allotment again picks up a quarrel with his/her neighbour and is found guilty, he/she shall be declared ineligible for further allotment of accommodation permanently and such declaration shall be made with the approval of the competent authority.

#### **23. Allotment of alternate accommodation or regularisation of accommodation in the name of a certain person in case of death of an allottee-**

(1) In the event of death of an allottee, the same accommodation may be regularized in the name of the spouse or ward of the deceased allottee, if the spouse or ward is entitled for it.

(2) In case, the entitlement of the spouse or ward is a lower type than the accommodation allotted to deceased allottee, an alternate entitled type of accommodation may be regularized in the name of spouse or ward.

(3) In case, the spouse or ward is entitled for higher type of accommodation than the accommodation allotted to the deceased allottee, an alternate one type below the entitled accommodation may be allotted to the spouse or ward subject to a maximum of Type V accommodation on payment of normal licence fee or fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) the spouse or ward had been residing with the deceased allottee for at least three years prior to the death of the allottee and has not drawn house rent allowance for this period and in case such spouse or ward is in the service of Lok Sabha Secretariat for less than three years, then he/she has not drawn house rent allowance since the date of his/her joining the Lok Sabha Secretariat service;
- (ii) the spouse or the ward joins the Lok Sabha Secretariat within a period of two years after the death of the allottee and the accommodation in occupation has not been vacated.

Explanation- For the purpose of this rule, “ward” shall include- (a) a married daughter, working in Lok Sabha Secretariat, irrespective of the fact that the deceased allottee is having a son,



- who is also employed in Lok Sabha Secretariat, and he is in a position to maintain the parents; (b) a daughter-in-law, working in Lok Sabha Secretariat;
- (iii) request for regularization/allotment of alternate accommodation may be considered in case the spouse/ward gets employment in Lok Sabha Secretariat even after the death of the allottee, provided the appointment is secured within a period of two years after the death of the allottee and the accommodation in occupation has not been vacated;
  - (iv) the above concession will be allowed in cases where the deceased Officer or spouse/ ward is not owning a house in Delhi/NCR;
  - (v) there are no arrears of licence fee/ damage outstanding against the deceased allottee;
  - (vi) the facility of regularisation or allotment of alternate accommodation shall be admissible under rules irrespective of the date of priority of the spouse or ward.
  - (vii) the application for regularisation or allotment of alternative accommodation shall be submitted before the expiry of the permissible period of retention after the date of death or from the date of appointment of the spouse or ward in Lok Sabha Secretariat service, whichever is later.
  - (viii) all dues outstanding in respect of the accommodation occupied by the deceased allottee shall be cleared before submission of the application for regularisation or alternate allotment.
  - (ix) the pay of the spouse or ward shall be taken into account for determining the entitled type of accommodation as per these rules on the date of regularisation of the spouse or ward.
  - (x) the alternate allotment in the name of the spouse or ward will be made, to the extent possible, in the same area, failing which in a nearby area.
  - (xi) the ward in whose name regularisation of alternate accommodation is to be made shall give an undertaking to the extent that the spouse of the deceased allottee, as the case may be, shall reside with such ward in the allotted accommodation after regularisation or after allotment of alternate accommodation.

**24. Allotment of alternate accommodation or regularisation of accommodation in the name of certain person in case of retirement of an allottee-**

- (1) In the event of retirement of an allottee, the same Lok Sabha Secretariat Pool accommodation may be regularised in the name of the spouse or ward of the retired allottee, if the spouse or ward is entitled for it.
- (2) In case, the entitlement of the spouse or ward is a lower type than the accommodation allotted to a retired allottee, an alternate entitled type of accommodation may be regularised in the name of spouse or ward.
- (3) In case, the spouse or ward is entitled for higher type of accommodation than the accommodation allotted to the retired allottee, an alternate one type below the entitled accommodation may be allotted to the spouse or ward subject to a maximum of Type V accommodation on payment of normal licence fee and on fulfilment of the following conditions:-
  - (i) the spouse or ward has been residing continuously for at least three years with the retiring allottee prior to his/her retirement and has not drawn house rent allowance for this period and in case such spouse or ward is in the service of Lok Sabha Secretariat for less than three years, then, he/she has not drawn house rent allowance since the date of his/her joining the Lok Sabha Secretariat service;
  - (ii) the spouse or ward joins the Lok Sabha Secretariat within the permissible period of retention and the accommodation in occupation has not been vacated.
- (4) In case of more than one eligible ward, the retiring official will have the option to exercise his/her choice in favour of his/her wards.

Explanation-For the purpose of this rule, "ward" shall include-

- (a) a married daughter, working in Lok Sabha Secretariat, irrespective of the fact that the retiring allottee is having a son, who is also employed in Lok Sabha Secretariat, and he is in a position to maintain the parents;
- (b) a daughter-in-law, working in Lok Sabha Secretariat.

**25. Non-admissibility for regularisation or alternate accommodation-**

The facility of regularisation or allotment of alternate accommodation under the above rules (23 and 24) shall not be admissible in the following cases:-

- (a) where the allottee or any member of his/her family owns a house in Delhi/NCR: Provided that either one type below accommodation or same accommodation may be regularised in the name of spouse or ward whose date of priority is covered on the date of retirement of the retiring allottee or on the date of death of the deceased allottee, irrespective of being a house-owner in Delhi/NCR subject to such conditions as applicable to house owning allottees and as per the guidelines issued by the Lok Sabha Secretariat from time to time;
- (b) where the allottee has become ineligible for allotment of accommodation, due to any reason, on or before the date of his/her death or retirement; and
- (c) in the event of resignation from Lok Sabha Secretariat.
- (d) in case where the allottee was in possession of Lok Sabha Secretariat Pool accommodation and the ward/spouse is not eligible for allotment of accommodation of Lok Sabha Secretariat Pool and/or vice-versa.

**26. Discretionary allotment of accommodation-**

Discretionary allotments to serving Lok Sabha Secretariat Officers shall be permitted only on medical and functional grounds. The discretionary allotment of accommodation for medical and functional grounds shall be governed by the guidelines issued by the Lok Sabha Secretariat from time to time.

**27. Inter-pool exchange of accommodation between Lok Sabha Secretariat Pool residential accommodation and General Pool-**

Inter-pool transfer of accommodation may be made on mutual consent of Lok Sabha Secretariat and Directorate of Estate.

**28. Surrender of an allotment of accommodation-**

- (1) An allottee may surrender an allotment of accommodation at any time during the allotment period.
- (2) An allottee who surrenders the accommodation shall not be considered again for allotment of accommodation for a period of one year from the date of such surrender.

**29. Maintenance of accommodation by the allottee-**

(1) The allottee to whom a residential accommodation has been allotted shall maintain the accommodation and premises in a clean condition and such allottee shall not grow any tree, shrubs or plants contrary to the instructions issued by the Government or by its maintenance agencies nor cut or lop off any existing tree or shrubs in any garden, courtyard or compound attached to the accommodation save with the prior permission in writing of the concerned maintenance agencies.

(2) Trees, plantation or vegetation, grown in contravention of this rule may be caused to be removed by the concerned maintenance agencies at the risk and cost of the allottee concerned.

**30. Cooperation with maintenance agencies by the allottees to carry out repair works-**

- (1) All allottees of accommodation will cooperate with respective maintenance agencies of residential accommodation in Government colonies in carrying out all kinds of repair or renovation works.
- (2) In case a complaint for non-cooperation is received from the maintenance agency against any allottee, strict action shall be taken against him/her as per these rules and the instructions issued by the Lok Sabha Secretariat from time to time.

**31. Misuse of accommodation for trade or business or any other unauthorised activity-**

- (1) The accommodation shall be used for residential purposes only by the allottee and other authorised persons as per these rules.
- (2) Action shall be taken against the allottee for unauthorised use of the allotted accommodation as per these rules and instructions issued by the Lok Sabha Secretariat/Directorate of Estate in this regard from time to time.

**32. Payment of requisite charge or fee to public utility services-**

- (1) The allottees of accommodation shall pay the charges and fees to all utility services such as electricity, water, gas etc., regularly on receipt of the bill for such payment.
- (2) In case an allottee has not paid the dues to the public utility authorities before vacation or surrender of the accommodation, vacation or surrender of accommodation shall not be accepted by the maintenance agency.

**33. Unauthorised constructions in Government colonies-**

(1) No unauthorised construction shall be allowed in Government residential colonies and the unauthorised constructions, if any shall be removed or demolished by the concerned maintenance agency or the Estate Officer notified under the Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1971(40 of 1971), as the case may be in accordance with the provisions of that Act.

(2) In case any further unauthorised construction is found in the accommodation of the same allottee, the accommodation provided to such allottee shall be cancelled from the date of inspection of the accommodation and he shall be debarred for allotment of accommodation for remaining period of service in future.

(3) The procedure for dealing with cases relating to unauthorised construction or encroachment in accommodation or public premises and the responsibilities of respective maintenance agencies shall be specified from time to time.

**34. Unauthorised occupation after cancellation of allotment-**

Where, after an allotment of accommodation has been cancelled or is deemed to have been cancelled under any provisions of these rules, the accommodation remains or has remained in occupation of the allottee to whom it was allotted or of any person claiming through, such allottee shall be liable to pay damages for use and occupation of the accommodation, services, furniture and garden charges, as may be determined by the Central Government from time to time.

**35. Issue of vacation notice and show cause notice to the allottees-**

(1) The vacation notice shall be issued to all the allottees of accommodation or to their families at least fifteen days before the date of expiry of the permissible period of retention.

(2) In case where the allottees have not vacated the quarters after expiry of permissible retention period, the concerned authority will issue show cause notice to such unauthorised occupants under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

**36. Disciplinary proceedings against persons who fail to vacate temporary allotment of accommodation-**

(1) The temporary accommodation allotted for marriage and other social purpose shall be vacated on expiry of the allotment period.

(2) In case of failure to vacate the allotted accommodation the matter shall be referred to the Estate Officer for appropriate disciplinary action against him/her and damages shall be charged for such unauthorised occupation.

**37. Subletting of accommodation –**

(1) The allottee shall reside in the accommodation allotted to him/her with his/her family and immediate relations.

(2) In case any relationship ceases by any order of court of law, such relation shall not reside with the allottee.

(3) The servant quarters, out-houses and garages may be used for the bonafide purposes only.

(4) The allottee who shares the accommodation with his/her family or immediate relations shall furnish prior intimation to the Lok Sabha Secretariat furnishing full particulars of his/her family members or immediate relations residing in the accommodation allotted to him/her:

Provided that the details of guests, if such guest is likely to stay for more than fifteen days in the accommodation, shall be intimated to the Lok Sabha Secretariat, intimating full particulars of the individual or individuals.

(5) If an Officer to whom a residence has been allotted unauthorisedly sublets the residence or charges rent from the sharer or erects any unauthorized structure in any part of the residence or uses the residence or any portion thereof for any purposes other than that for which it is meant or tampers with the electric or water connection or commits any other breach of these rules or of the terms & conditions of the allotment or uses the residence or premises or permits or suffers the residence or premises to be used for any purpose which the Estate Officer considers to be improper or conducts himself/herself in a manner which in his/her opinion is prejudicial to the maintenance of harmonious relations with his/her neighbours or has knowingly furnished incorrect information in any application or written statement with a view to securing the allotment, the Estate Officer may, without prejudice to any other disciplinary action that may be taken against him/her, cancel the allotment of the residence:

Explanation.-In this sub-rule, the term "allottee" includes, unless the context otherwise required, a member of his/her family and any person claiming through the allottee.

(6) If an Officer sublets a residence allotted to him/her or any portion thereof or any of the out-houses or garages thereto, in contravention of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against

him/her, be charged enhanced licence fee as per rules. The quantum of licence fee to be recovered and the period for which the same may be recovered in each case will be decided by the Estate Officer on merits. In addition, the Officer may be debarred from sharing the residence for a specified period in future as may be decided by the Estate Officer.

(7) Where action to cancel the allotment is taken on account of unauthorized subletting of the premises by the allottee, a period of sixty days shall be allowed to the allottee, and any other person residing with him/her therein to vacate the premises. The allotment shall be cancelled with effect from the date of vacation of the premises or expiry of the period of sixty days from the date of the orders for the cancellation of the allotment, whichever is earlier.

(8) The Estate Officer shall be competent to take all or any of the actions under sub-rules (5) to (7) of this Rule and also to declare the Officer, who commits a breach of these rules or of the instructions issued to him/her, to be ineligible for allotment of residential accommodation for a period not exceeding three years.

(9) Where any penalty under this rule is imposed by the Estate Officer, the aggrieved person may, within twenty one days of the receipt of the order by him/her imposing the penalty, file a representation to the Secretary-General of the Lok Sabha through the Estate Officer.

(10) The Lok Sabha Secretariat shall be competent to- a) take all or any of the actions provided under this rule; and b) declare the allottee to be ineligible for allotment of residential accommodation for the remaining period of his/her service;

(11) The procedure to conduct subletting inspections by the authorised officials shall be such as may be specified by the Lok Sabha Secretariat from time to time.

(12) Cancellation of allotment of accommodation or otherwise of the cases suspected of subletting shall be decided by the competent authority after inquiry providing equal opportunity to the allottee.

### **38. Payment of licence fee for accommodation-**

(1) The rates of licence fee shall be charged from allottees and other ineligible officer or organisation for allotment of Lok Sabha Pool accommodation at such rates as may be specified by the Government/Lok Sabha Secretariat from time to time.

(2) Where the allotment of accommodation or alternative accommodation has been accepted, the liability for licence fee shall commence from the date of physical occupation of the accommodation.

(3) An allottee who, after acceptance, fails to take possession of that accommodation within five working days from the date of receipt of the authority letter shall be charged one month licence fee from the date of allotment:

Provided that this provision shall not apply in case the maintenance agency does not hand over the accommodation in a habitable condition to the allottee within the prescribed period or the accommodation is not ready for physical occupation for any other reason.

(4) The allottee to whom an accommodation has been allotted shall be personally liable for the payment of licence fee and for any damage beyond fair wear and tear caused thereto or to the furniture, fixture or fittings or services provided therein by the Government during the period for which the accommodation has been and remains allotted to him/her, or where the allotment has been cancelled under any of the provisions of these rules, until the accommodation along with the out-houses appurtenant thereto have been vacated and full vacant possession thereof has been restored to Lok Sabha Secretariat.

(5) The rates of damages for unauthorised occupation or subletting or misuse of accommodation, servant quarter or garage shall be specified by the Lok Sabha Secretariat from time to time.

(6) All the allottees of accommodation shall pay the requisite licence fee in advance for retention of the accommodation allotted to them.

(7) Where the allottee to whom an accommodation has been allotted is neither a permanent nor a quasi-permanent Government servant, he shall execute a surety bond in the form prescribed in this behalf by the Lok Sabha Secretariat with a surety who shall be a permanent Officer of the Lok Sabha Secretariat for due payment of licence fee and other charges due from him/her in respect of such accommodation and any other accommodation provided in lieu.

(8) If the surety ceases to be in service of Lok Sabha Secretariat or becomes insolvent or ceases to be available for any other reasons, the allottee shall furnish a fresh bond executed by another surety within thirty days from the date of his/her acquiring knowledge of such event or fact; and if he fails to do so, the allotment of the accommodation to him/her shall, unless otherwise decided by the Secretary-General of Lok Sabha, be deemed to have been cancelled with effect from the date of that event.

### **39. Continuance of allotment made prior to these rules-**

Any valid allotment of a residence which immediately before the commencement of these rules is subsisting under the rules then in force shall be deemed to be an allotment duly made under these rules notwithstanding that the

officer to whom it has been made is not entitled to a residence of that type under Rule and all the provisions of these Rules, shall apply in relation to that allotment and that officer accordingly.

**40. Interpretation –**

If any question arises relating to the interpretation of the Rules, it shall be referred to the Speaker of the Lok Sabha for decision.

**41. Power to relax rules-**

The Speaker may relax all or any of the provisions of these rules in the case of any officer or residence or class of officers or type of residences.

**42. Delegation –**

The Secretary-General of the Lok Sabha may, from time to time, by general or special order, direct that any power exercisable by him/her under these rules (except the powers under this rule) shall, subject to such conditions, if any as may be specified in the order, be exercisable also by such officer of the Lok Sabha Secretariat as may be specified in the order.

[F. No. 022/1/2022/213952]

SIDDHARTH MAHAJAN, Jt. Secy.

**Notification:** The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 576, dated the 1<sup>st</sup> May, 1974 and subsequently amended *vide* the following numbers:

1	G.S.R. 279(E), dated 17 <sup>th</sup> June, 1977
2	G.S.R. 566(E), dated 1 <sup>st</sup> December, 1978
3	G.S.R. 439(E), dated 7 <sup>th</sup> July, 1979
4	G.S.R. 1110(E), dated 26 <sup>th</sup> September, 1986
5	G.S.R. 1011(E), dated 22 <sup>nd</sup> December, 1987
6	G.S.R. 3(E), dated 1 <sup>st</sup> January, 1997
7	G.S.R. 67 (E), dated 6 <sup>th</sup> February, 1997
8	G.S.R. 142(E), dated 20 <sup>th</sup> March, 1998
9	G.S.R. 247(E), dated 6 <sup>th</sup> May, 1998
10	G.S.R. 621(E), dated 14 <sup>th</sup> October, 1998
11	G.S.R. 81(E), dated 8 <sup>th</sup> February, 1999
12	G.S.R. 742(E), dated 13 <sup>th</sup> October, 2008
13	G.S.R. 314(E), dated 3 <sup>rd</sup> May, 2009
14	G.S.R. 799(E), dated 26 <sup>th</sup> December, 2013
15	G.S.R. 259(E), dated 20 <sup>th</sup> February, 2017